संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 साप्त् 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH·ONE FAMILY·ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

12th February, 2024

DO No. 07/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague.,

Last week, I attended the Roundtable at the Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific (RILO A/P) in Tokyo, Japan. The RILO A/P, under the framework of the World Customs Organization (WCO), serves as the focal point of intelligence analysis and liaison of enforcement cooperation with Customs administrations in the Asia and Pacific region. This High-Level Roundtable was centred on the Enhancement of Data/Intelligence Analysis and Regional Cooperation Networks. While the Roundtable was well-structured and productive, it also gave me a chance to have bilateral interaction with the Secretary General, World Customs Organization, the Secretary General, CITES and Director General, Customs & Tariff Bureau, Japan. These interactions will help me understand first-hand the areas where we can work together. Additionally, the Japanese culture, their traditions, values and attention to detail have deeply resonated with me on a personal level.

Recently, the Directorate General of GST Intelligence (DGGI) has brought to light a concerning trend involving fraudulent individuals issuing fake summons to taxpayers, whether or not they are under investigation by the DGGI. These fake summons, despite bearing a Document Identification Number (DIN), are not authorized by the DGGI for the entities whose names are mentioned therein. In response to this, the DGGI has taken decisive action, including informing and filing complaints with the police against those responsible for generating and disseminating these deceptive summons. It's crucial for individual taxpayers who receive suspicious or potentially fake summons from DGGI formations to promptly report them to the relevant jurisdictional DGGI or CGST office for verification and necessary action. This proactive approach will ensure that appropriate measures can be taken against the perpetrators of these fraudulent activities, safeguarding the integrity of the taxation system.

Last week, I noticed that Mumbai Customs, Zone-III officers destroyed narcotic substances weighing almost 14 MTs by incinerating them at a waste

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

disposal facility near Mumbai. Such actions amplify the resolve of CBIC towards the goal of नशा मुक्त भारत.

On the enforcement front, Kolkata Customs has cracked a novel modus. It was gathered by the officers of the Special Investigation & Intelligence Branch (Port), Kolkata Customs, that the exporters of dutiable rice are getting payments over and above the declared value in the guise of purported export-duty reimbursement from overseas buyers. This reimbursement led to the manipulation of the transaction value of the export goods. The exporter has taken the value as cum-duty-price and excluded the purported duty component, which was being reimbursed from the overseas buyers, leading to short payment of customs duty. During the investigation against 31 exporters by Kolkata Customs so far, approximately Rs. 9.1 Crore has been recovered.

Further, I would like to mention the appreciable efforts of the officers of DRI Lucknow Zonal Unit, who recovered and seized 679 live baby Gangetic turtles. DRI Lucknow has seized 2551 Gangetic turtles so far. Great work!

Till next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

12th February, 2024

DO No. 07/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

पिछले सप्ताह, मैंने टोक्यो, जापान में रीजनल इंटेलिजेंस लायसन ऑफिस फॉर एशिया एंड पसिफ़िक (RILO A/P) के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के ढांचे के तहत RILO A/P, जो एशिया एंड पसिफ़िक क्षेत्र में सीमा शुल्क प्रशासन के साथ खुफिया विश्लेषण और प्रवर्तन सहयोग के संपर्क के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है । यह उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन डेटा/इंटेलिजेंस विश्लेषण और क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क को बढ़ाने पर केंद्रित था। गोलमेज बैठक सुव्यवस्थित और उत्पादक थी और इसने मुझे महासचिव, विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO), महासचिव, सीआईटीईएस (CITES) और महानिदेशक, सीमा शुल्क और टैरिफ ब्यूरो, जापान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने का मौका भी दिया। ये बातचीत मुझे उन क्षेत्रों को सीधे तौर पर समझने में मदद करेगी जहां हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जापानी संस्कृति, उनकी परंपराएं, मूल्य और विस्तार पर ध्यान ने व्यक्तिगत स्तर पर मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है।

हाल ही में, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने करदाताओं को फर्जी समन जारी करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से संबंधित एक चिंताजनक प्रवृत्ति को प्रकाश में लाया है, चाहे वे डीजीजीआई द्वारा जांच के अधीन हों या नहीं। दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) होने के बावजूद, ये नकली समन उन संस्थाओं के लिए डीजीजीआई द्वारा अधिकृत नहीं हैं जिनके नाम उनमें उल्लिखित हैं। इसके जवाब में, डीजीजीआई ने निर्णायक कार्रवाई की है, जिसमें इन भ्रामक सम्मनों को तैयार करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचित करना और शिकायत दर्ज करना शामिल है। जिन व्यक्तिगत करदाताओं को डीजीजीआई संरचनाओं से संदिग्ध या संभावित रूप से फर्जी समन प्राप्त होते हैं, उनके लिए सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले डीजीजीआई या सीजीएसटी कार्यालय को तुरंत रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। यह सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि कराधान प्रणाली की अखंडता की रक्षा करते हुए, इन धोखाधड़ी गतिविधियों के अपराधियों के खिलाफ उचित उपाय किए जा सकें।

पिछले सप्ताह, मैंने देखा कि मुंबई सीमा शुल्क, ज़ोन-III अधिकारियों ने लगभग 14 मीट्रिक टन वजन वाले नशीले पदार्थों को मुंबई के पास एक अपशिष्ट निपटान सुविधा में जलाकर नष्ट कर दिया। इस तरह की कार्रवाइयां 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य की दिशा में सीबीआईसी के संकल्प को बढ़ाती हैं।

प्रवर्तन के मोर्चे पर, कोलकाता सीमा शुल्क ने एक नवीन कार्य प्रणाली को ढूँढा है। विशेष जांच और खुफिया शाखा (पोर्ट), कोलकाता सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा यह पता चला कि शुल्क योग्य चावल के निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से कथित निर्यात-शुल्क प्रतिपूर्ति की आड़ में घोषित मूल्य से अधिक भुगतान

मिल रहा है। इस प्रतिपूर्ति के कारण निर्यात वस्तुओं के लेनदेन मूल्य में हेरफेर हुआ। निर्यातक ने मूल्य को सह-शुल्क-मूल्य (cum-duty-price) के रूप में लिया है और कथित शुल्क (duty component) को बाहर रखा है, जिसकी प्रतिपूर्ति विदेशी खरीदारों से की जा रही थी, जिससे सीमा शुल्क का कम भुगतान हुआ। कोलकाता कस्टम्स द्वारा अब तक 31 निर्यातकों के खिलाफ जांच के दौरान लगभग 9.1 करोड़ रुपये मिला है।

इसके अलावा, मैं डीआरआई लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने 679 जीवित शिशु गंगा कछुओं को बरामद किया और जब्त किया। डीआरआई लखनऊ ने अब तक 2551 गंगा कछुए जब्त किए हैं। बहुत बढ़िया !

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।